राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/शिका)विभाग

विषयः– लम्बित अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणो के संबंध में मान0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 25.07.16 की पालना के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 2642/2005 पूनम चंद भण्डारी बनाम सरकार व जनहित याचिका संख्या 18408/2012 में पारित आदेश दिनांक 25.07.16 द्वारा विभिन्न विभागों में अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों के लम्बे समय तक लम्बित रखे जाने को गम्भीरता से लेते हुए विभिन्न विभागों में लम्बित प्रस्तावो का पूर्ण विवरण मय औचित्य सहित सशपथ चाहा है। मान0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका दिनांक 02.11.12 के आदेश एवं दिनांक 31.03.15 के आदेश का हवाला देकर विभिन्न विभागो में प्राधिकृत अधिकारियों (Competent authorities) के स्तर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में अभियोजन के लम्बित प्रकरणों का पूर्ण विवरण एवं उनके लम्बित रहने के औचित्य का विवरण दिनांक 12.08.16 तक प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये है एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु 22.08.16 को रखा गया है।

अतः समस्त विभागो के अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी संशोधित प्रारूप में सूचना एवं शपथ पत्र दिनांक 09.08.16 से पूर्व प्रेषित करें।

भवदीय

(ओ.पी.मीना)
मुख्य सचिव,

अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अशा.टीप 6(5)का/क–3/शिका/12
जयपुर, दिनांकः 08.08.16
नोटः–प्रारूप एवं शपथ पत्र कार्मिक विभाग की बेवसाईट पर अपलोड है।

शपथ पत्र

मैं.................................. हाल पदस्थापन अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,.............................. विभाग शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैंने माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका (डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं0. 2642/2005 एवं 18408/2012) के अन्तर्गत दिनांक 25.7.2016 को जारी आदेश का अध्ययन कर लिया है।

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि .... विभाग में (जिसका कि मैं वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव हूँ), दिनांक........... को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत कुल........ प्रकरण अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु लम्बित हैं, जिनका विवरण मय औचित्य निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	आरोपित अधिकारी का नाम मय पद	अपराध सं0	अपराध की धाराएं	किस दिनांक से लम्बित	लम्बित रहने का औचित्य

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं.............................. हाल पदस्थापन अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, ...विभाग, सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना विभागीय रिकॉर्ड एवं मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

सत्यापनकर्ता

<u>प्रपत्र</u>

<u>भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लम्बित अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणो का विवरण</u>

क.स.	अपराध संख्या	विभाग का नाम	आरोपित अधिकारी का नाम	आरोप का विवरण	किस दिनांक से लम्बित है।	प्रकरण लम्बित रहने का औचित्य	अधिकारी का स्तर (राज्य सेवा/अधिनस्थ सेवा)

In The High Court of Judicature for Rajasthan
Jaipur Bench, Jaipur

ORDER

D.B. Civil Writ Petition (PIL) No.18408/2012
D.B. Civil Writ Petition (PIL) No.2642/2005

Date :: 25-7-2016

Hon'ble Mr. Justice Ajay Rastogi
Hon'ble Mr. Justice J.K. Ranka

Mr. S.S. Hora Adv. with]
Mr. Dharmendra Saini Adv.,]
Mr. Abhinav Bhandari Adv.] for petitioners.
Mr. N.M. Lodha Advocate General with]
Mr. Vishal Sharma Adv.,]
Mr. Anurag Sharma AAG] for respondents.

We are going ahead with the sorry state of affairs that despite means & measures being adopted still the corruption which is rampant going on could not be curbed & this is also the public perception which is being strengthened by the information made available to the public through newspapers. In S.B. Criminal Misc. 2nd Bail Application No.9673/2012 this Court took cognizance of the matter & directed the State Government to inform regarding the matters under the Prevention of Corruption Act pending with the respective concerned competent authorities for sanction of prosecution & under the directions of this Court it came to be registered as PIL Petition and the proceedings reveals that detailed orders were passed by this Court time and again calling upon the State Government to furnish the details and it reveals that after passing the initial detailed order dt.2-11-2012, almost three years & eight months have rolled by now and still we have not been able to reach to any prima facie conclusion so far and at least three

status reports have been furnished by the Government which is nothing but a repetition of its previous version and the matter for one reason or the other was adjourned on the premise of status report being furnished & even that also does not justify as to why these matters are pending with the respective authorities for almost 4-5 years, out of which one case is pending since 2007 but still sanction of prosecution could not be granted and it goes without saying that the delay in granting sanction of prosecution in the matters of prevention of corruption frustrate the very purpose & object of the mandate of the Act since only after the sanction of prosecution being granted by the competent authority & after filing challan & after framing of charge, the trial commences and that certainly takes time.

Taking note of the order by which cognizance was taken treating it to be Public Interest Litigation dt.2-11-2012 we direct the State Government to comply order of the Court dt.2-11-2012 followed with 31-3-2015 and furnish the complete details of pending cases under the Prevention of Corruption Act with the respective competent authorities for grant of sanction for prosecution and we make it clear that this order may not be confined to the information from the DOP only, it shall be from all the concerned departments & authorities competent to grant sanction of prosecution in respect of the matters under the Prevention of Corruption Act and at the same time the respondents shall also specify the justification for which the matters remain

pending for sufficient long time with the Government.

Let the affidavit with complete details, of which we have made a reference (supra), signed by a responsible officer not below the rank of Principal Secretary/Secretary of the department, be furnished to this Court within two weeks, with advance copy to petitioner's counsel who is requested to assist the Court in the matter, that apart as directed, let a copy of this order be sent to the Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur for taking necessary action/steps for compliance.

Let the matters may come up before the Court on 22-8-2016, as prayed.

(J.K. Ranka),J.

(Ajay Rastogi),J.

प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर